

## RAJYA SABHA

Monday, 16th December, 1991-25 Agrahayana, 1913 (Saka)

The House met at eleven of the Clock,  
Mr. Chairman in the Chair.

### ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**उत्तर प्रदेश में बहराइच में पर्यटक गृह का निर्माण**

\*341. श्री आनन्द प्रकाश गौतम :  
क्या नागर विमानन और पर्यटक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में श्रावस्ती बुद्ध स्थल के निकट एक उत्तम किस्म के पर्यटक गृह के निर्माण के लिये 13.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहाँ अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इस परियोजना के लिये कितना धन उद्दिष्ट किया गया है तथा अब तक कितना धन दिया जा चुका है ; और

(ङ) इसके निर्माण के लिये कब तक का समय निर्धारित किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अ० एल० फारूख) : (क) से (ङ) एक विवरण सभापति पर रख दिया गया है ।

#### विवरण

(क) जी हाँ, सरकार ने एक पर्यटक परिसर का निर्माण करने के लिए 12.583 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निर्माण करने पर आपत्ति इस आधार पर की थी कि अधिग्रहीत भूमि को संरक्षित/प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है ताकि प्राचीन स्थल और इसके पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके ।

(घ) पर्यटक परिसर 63.00 लाख रुपए की लागत पर अनुमोदित किया गया था और भारत पर्यटन विकास निगम को निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए 20.00 लाख रुपए आवमुक्त किए गए थे ।

(ङ) इस परिस्थिति में निर्माण कार्य के लिए कोई समयबद्ध निर्धारित कर पाना कठिन है ।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : माननीय सभापति महोदय, पर्यटन की दृष्टि से हमारे देश के पर्यटन स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और शायद इसी दृष्टिकोण से भारतीय पर्यटन विकास निगम ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में श्रावस्ती बुद्ध स्थल पर एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बनाने का निर्णय लिया था । अभी जो प्रश्न का उत्तर आया है उसमें यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहाँ पर जो भूमि अधिग्रहीत की है उस पर निर्माण कार्य करने पर इस आधार पर आपत्ति की है कि भूमि को संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है ।

मंत्री महोदय से बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर चाहूंगा कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है वह प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने के बारे में, और पर्यटन स्थल के बनाने के बारे में जो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है वह कार्रवाई सम्पन्न हो गई है अथवा नहीं हुई है ? और इसके सम्पन्न होने में जो काश्तकारों को मुआवजा देने की बात है और भूमि को अपने कब्जे में लेने की बात है तो क्या यह कार्रवाई हो चुकी है ? और तीसरे उसके बाद यह नोटिस दिया गया है कि यहाँ पर इस को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है या नहीं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : सर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जब आपत्ति उठाई तो उसके पश्चात् एक उच्च स्तरीय टीम ने दुबारा एक वैकल्पिक साइट सोचने का प्रयास किया। उसको आइडेंटिफाई करके प्रदेश सरकार को यह जानकारी दी गई। यह नवम्बर, 1988 में टीम गई थी। इसके पश्चात् कई रिमाइन्डर्स भेजे गये और काफी रिमाइन्डर्स के पश्चात् स्टेट गवर्नमेंट ने यह जानकारी हमें दी कि ग्रब स्टेट पी०डब्ल्यू०डी० जिसकी जमीन थी वह अब इस जमीन को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। क्योंकि यह निःशुल्क जमीन आई०टी०डी०सी० को दी जानी थी इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने हम को यह भी जानकारी दी कि 11.42 लाख रुपये पी०डब्ल्यू०डी० को दे दिये गये हैं। पर अभी भी अतिरिक्त भूमि लेने से रह गई है जो लगभग साढ़े 4 एकड़ है जिसका अधिग्रहण अभी नहीं हुआ, ट्रांसफर अभी नहीं हुआ और इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट से। उनको याद दिला रहे हैं पर जो पर्याप्त एक रिस्पॉस उनका होना चाहिए वह हमें नहीं मिल रहा है। तो शायद इसलिए हो सकता है कि प्रदेश सरकार ने दूसरी भूमि अधिग्रहण की है और वहां वे प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रण दे रहे हैं। उनसे चर्चा हो रही है। होटल लगाने की बात हो सकती है और यहीं इसका कारण हो। परन्तु हम लोगों की तरफ से पूरा प्रयास है कि इसको विकसित किया जाये। जब तक हमको जमीन उपलब्ध नहीं होगी तब तक विकसित करने का सवाल नहीं उठता क्योंकि हम शुरुआत का कार्य नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक धनराशि का सवाल है, माननीय सदस्य को जवाब में जानकारी दे दी गई है कि 63 लाख रुपये इसके लिए स्वीकृत किये गये हैं और 20 लाख रुपये आई०टी०डी०सी० को डिपार्टमेंट आफ टूरिज्म कई वर्ष पहले दे चुका है। हम लोग कार्य शुरू करने के लिए तैयार हैं। अगर जमीन जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो तो हम कार्य शुरू कर पाएंगे।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : इस बात की जानकारी माननीय मंत्री जी की तरफ से नहीं आई है कि इस योजना में अधिग्रहण की कार्यवाही को कब शुरू किया गया था? यह प्रश्न मैंने पहले पूछ लिया था कि यह कार्यवाही आपने कब शुरू की है और इसको कितना समय हो गया है, अभी तक इसमें कार्यवाही नहीं की गई है। अगला प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि जो भूमि संरक्षित करके प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित करने की कोशिश की गई है और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि दूसरे स्थल पर पर्यटन स्थल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है और यह जो दूसरी योजना बनी है उसमें वे कितनी भूमि लेना चाहते हैं? क्या उस भूमि का कोई निर्देशन हुआ है और अगर वह भूमि प्राइवेट सेक्टर की है तो उसके अधिग्रहण की कार्यवाही का क्या कोई प्रारम्भिक कार्य हुआ है?

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय, मैं कह चुका हूँ कि जो वैकल्पिक भूमि है उसका क्षेत्र लगभग 6 एकड़ है और इसमें से लगभग साढ़े चार एकड़ भूमि अभी भी बकाया है और कुछ धनराशि जो पी०डब्ल्यू०डी० को दी गई है वह साढ़े चार एकड़ मिलने के पश्चात् छः एकड़ में से है। जो पैमेन्ट हुई है वह जमीन अभी नहीं दी गई है। अतिरिक्त साढ़े चार एकड़ की भी पैमेन्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो जाएगी तो उसके पश्चात् ही जमीन ट्रांसफर की जाएगी और तभी कार्य शुरू कर सकते हैं। नवम्बर, 1988 में हमारी हाई लेवल टीम वहाँ गई थी, तब से स्टेट गवर्नमेंट के साथ चर्चा चल रही है। यह काफी पुराना मामला है। दिसम्बर 1988, जनवरी 1989, अप्रैल 1989, जून 1989, अगस्त 1989, दिसम्बर, 1989 और सितम्बर, 1990 में हमने रिमाइन्ड किया है। मैं मान यह संकेत दे रहा हूँ कि बहुत गम्भीरता हम इस प्रोजेक्ट को दे रहे हैं। हमारा पूरा निर्णय है कि इसको विकसित करें। इसके लिए जमीन मिलना अति आवश्यक है और अनिवार्य है।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : मैंने यह जानना चाहा था कि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हुई है या नहीं ?

श्री माधव राव सिधिया : जैसा मैंने कहा, अधिग्रहण स्टेट गवर्नमेंट को करना है। 11.42 लाख रुपये दे दिये गये हैं। अधिग्रहण स्टेट गवर्नमेंट को करना है और उसके बाद ही जमीन ट्रांसफर होगी।

श्री बेकल "उत्साही" : हमारे अजीज दोस्त गौतम साहब ने सही कहा है कि यह बुद्ध स्थली निहायत ही अहम हैं। हम तो वहीं 6-7 किलोमीटर पर रहते हैं और अच्छी तरह से इस बारे में जानते हैं। इसके पहले जब मैं टुरिज्म विभाग की कंसल्टेटिव कमिटी में था तो मैंने कई सजेरशन्स दिये मैं और एक रनवे बनाने का भी सजेरशन दिया था, जो स्वीकार किया गया था। यह श्रावस्ती वह स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने बैठ कर 24 वर्ष तक अपने भिक्षुओं को दीक्षा और शिक्षा दी थी। इस तरह से वह बड़ा अहम और जरूरी स्थान है। जिसको डेवलपमेंट दिया जाये और विकसित किया जाये। हम जानते हैं कि जो जमीन एक्वायर की गई थी वह बिल्कुल अलग-अलग थी। हमारे पुरातत्व विभाग के लोगों ने न जाने क्यों इसको रोका और आपत्ति की। अब जो जमीन एक्वायर की जा रही है, वहाँ पर पी०डब्ल्यू०डी० का स्टेट हाउस है। वहाँ पर हमारे यात्री आते हैं। वह बहुत ही खराब हालत में है, उसमें रहते हैं, इसका दूसरे देशों पर क्या असर पड़ता होगा ? इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वह रनवे स्वीकार हो चुका है और उसके निर्माण का क्या सिलसिला है ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पर्यटन विभाग द्वारा जो योजना बनाई जा रही है उसके लिए भूमि बहुत ही नाकामो है, यह बात माननीय मंत्री जी ने भी कही है। उसके विकास के लिए हमारे पुरातत्व विभाग के और जापान के पुरातत्व स्कालर भी गये थे और खुदाई भी कर रहे थे।

श्री बिकल "उत्साही" : हमारे अजीज दोस्त गौतम साहब ने सही कहा है कि यह बुद्ध स्थली निहायत ही अहम हैं। हम तो वहीं 6-7 किलोमीटर पर रहते हैं और अच्छी तरह से इस बारे में जानते हैं। इसके पहले जब मैं टुरिज्म विभाग की कंसल्टेटिव कमिटी में था तो मैंने कई सजेरशन्स दिये मैं और एक रनवे बनाने का भी सजेरशन दिया था, जो स्वीकार किया गया था। यह श्रावस्ती वह स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने बैठ कर 24 वर्ष तक अपने भिक्षुओं को दीक्षा और शिक्षा दी थी। इस तरह से वह बड़ा अहम और जरूरी स्थान है। जिसको डेवलपमेंट दिया जाये और विकसित किया जाये। हम जानते हैं कि जो जमीन एक्वायर की गई थी वह बिल्कुल अलग-अलग थी। हमारे पुरातत्व विभाग के लोगों ने न जाने क्यों इसको रोका और आपत्ति की। अब जो जमीन एक्वायर की जा रही है, वहाँ पर पी०डब्ल्यू०डी० का स्टेट हाउस है। वहाँ पर हमारे यात्री आते हैं। वह बहुत ही खराब हालत में है, उसमें रहते हैं, इसका दूसरे देशों पर क्या असर पड़ता होगा ? इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वह रनवे स्वीकार हो चुका है और उसके निर्माण का क्या सिलसिला है ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पर्यटन विभाग द्वारा जो योजना बनाई जा रही है उसके लिए भूमि बहुत ही नाकामो है, यह बात माननीय मंत्री जी ने भी कही है। उसके विकास के लिए हमारे पुरातत्व विभाग के और जापान के पुरातत्व स्कालर भी गये थे और खुदाई भी कर रहे थे।

پریشن و بھاگ دنیا جو روڑا بنائی جا رہی ہے اس کے لیے بھولی بہت ہی ناکافی ہے۔ یہ بات ماننے کی منتری جی نے ہی کی ہے۔ اس کے وکاس کے لیے ہمارے براؤڈ ویجاگ کے اور جاپان کے براؤڈ اسکاڑ بھی گئے تھے اور کھدائی بھی کی ہے تھے۔

وہ بھی یہ تہ نہیں کر سکے کہ آیا گوتام بুদ্ধ، مہاتما گوتام وہاں پر تھے یا نہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں۔۔۔

شری بیکن "انسائی" وہ بھی ملے نہیں کہہ سکتے کہ کیا گوتام بুদ্ধ۔ مہاتما گوتام وہاں پر تھے یا نہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں۔

श्री सभापति : इसने अभी तय नहीं किया कि महत्मा बुद्ध वहाँ गये थे या नहीं। अभी भी कोई डाउट है क्या ?

श्री बेकल "उरसाही" : वहाँको डाउट है। इसीलिए कि वे कहते हैं कुशाण पौरियड और गुप्त पौरियड की सारी चीजें मिल रही हैं। उससे पहले का तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। हमारे खद के पुरातत्व वाले वहाँ गये थे। जापान के स्कालर अभी तक इन मंजिल पर पहुँचे ही नहीं हैं जो वह यह साबित कर सकें कि महत्मा बुद्ध वहाँ बैठे भी थे। वह दो हिस्सों में बँटा हुआ है। एक तो वह है जिसको हम अपनी जवान में सहेट कहते हैं और दूसरा है सहेट। बीच में किसी वक्त नदी बहती थी। यह इतना बड़ा स्थान है लेकिन वहाँ पर टुरिज्म विभाग है ही नहीं। सिर्फ हाटिकलवर के लोग हैं जो कुछ पीछे लगा रहे हैं। ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि स्टेट और सेंटर इन दो पदों के बीच में यह स्थान पिस रहा है और

उसका डवलपमेंट रुक रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि कब तक इसको आप विकसित करेंगे ?

श्री بیکن "انسائی" ان کو ڈاؤٹ ہے۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کشان پیرینڈ اور گپت پیرینڈ کی ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ اس سے پہلے کا تو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے۔ ہمارے خود کے پراہتو والے وہاں گئے تھے۔ جاپان کے اسکالر ابھی تک اس منزل پر پہنچے ہی نہیں ہیں۔ جو وہ یہ ثابت کر سکیں کہ مہاتما بুদ্ধ وہاں بیٹھے بھی تھے۔ وہاں دو جمنوں میں بٹا ہوا ہے ایک تو وہ ہے جس کو ہم اپنی زبان سے سہٹ کہتے ہیں اور دوسرا ہے

مہٹ بیچ میں کسی وقت ندی بہتی تھی۔ یہ اتنا بڑا استھان ہے لیکن وہاں پر ٹورزم و بھاگ ہے ہی نہیں صرف بارنی کلچر کے لوگ ہیں جو کچھ بودے لگا رہے ہیں ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ اور سینٹر ان دو پارتوں کے بیچ میں یہ استھان پیس رہا ہے اور اس کا ڈیولپمنٹ رک رہا ہے میں منتری ہر دسے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب تک اس کو آپ وکسٹ کریں گے۔

SHRI M.O.H. FAROOK : Sir we share the views of the hon. Member about the importance of this Place They have no doubt about the genuineness of the place. As far as we are concerned, we have no doubt about the

genuineness of the place. It all depends upon the State Government to provide us the land. As soon as they provide us the land, we will take necessary steps.

MR. CHAIRMAN : He wants to know about the air strip.

SHRI M.O.H. FAROOK : There is no proposal for an air strip.

श्री माधव राव सिधिया : जहाँ तक एयर स्ट्रिप का सवाल है पूरा क्षेत्र जो है, परम पूजननीय गौतम बुद्ध जहाँ-तहाँ गये थे, जहाँ-तहाँ उन्होंने निवास किया, जापान की एक योजना है उसके अन्तर्गत यह आ रहा है। इनमें एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और एक हिस्सा बिहार में है। श्रावस्ती भी इसी स्कीम के अन्तर्गत आती है। इन लोगों ने भी प्रपोजल रखा था कि श्रावस्ती में एयर पोर्ट भी हो और रनवे भी हो। पर जपानी टीम, जिसने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गंभीरता से इसकी स्टडी की है उनका यह कहना है कि वहाँ पर रनवे बेस्वीकृत करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको बहुत बड़ी स्कीम है। लगभग 170 करोड़ रुपये की वह स्कीम है। जपानी टीम ने इस प्रपोजल को रजेक्ट कर दिया है। इसलिये वहाँ पर अभी कोई रनवे का प्रपोजल नहीं है।

श्री संघ प्रिय गौतम : माननीय सभापति महोदय, भारत अपनी संस्कृति के लिये सारे विश्व में बहुत पुराने समय से जाना जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध के दर्शन और उनके संदेश ने भारत को सारे संसार में गौरवान्वित किया है। मेरे दोस्तों ने अभी बताया कि वर्षों तक महत्त्वा गौतम बुद्ध ने वहाँ पर दीक्षार्थ और शिक्षार्थ दी और पंचशील की उन्होंने सारे संसार में ध्वजा फहराई। उसी पंचशील के नारे को लेकर तत्कालीन चीन के प्रधान मंत्री और पंडित नेहरू के बीच संधि हुई। आज भी चीन के प्रधानमंत्री ली-फांग ने भी पंचशील को बोहराया है। महोदय, वैसे भी यह बाबा साहेब अम्बेडकर शती वर्ष है कि उन्होंने बुद्ध धर्म का पुनरुत्थान इस देश में किया। तो मेरा मंत्री जी ने प्रश्न है कि जब बौद्ध धर्म इतना सार्थक उस समय था और आज भी अब इसकी महत्ता बढ़

रही है और बौद्ध धर्म के मानने वाले देशों से इतनी भारी संख्या में पर्यटक रहें अते हैं तो क्या यह सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वह इस स्थान का विहास करे और वहाँ पर हवाई पट्टी बनाये, टूरिस्ट होम बनाये? यह जो बहुधा करते हैं कि इसमें लैंड एक्विजिशन की परेशानी है तो

I want to remind the hon. Minister that section 17 of the Land Acquisition Act of Uttar Pradesh authorises the Government to take immediate possession.

तो आप क्यों नहीं उसका तुरंत पत्रेक्षण लेते हैं, क्यों नहीं उसका मन्त्रवक्ता आप तय करते हैं?... (व्यवधान)

श्री बी० नारायणस्वामी : लैंड एक्विजिशन ऐक्ट की बात नहीं है... (व्यवधान)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM : Listen to me.

This is part (a) of my question. Part (b)

of my question is :

माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान) ... वहाँ पर श्रीलंका द्वारा संगठित एक इंटरमीडिएट विद्यालय बना हुआ है, वहाँ पर बौद्ध विहार बना हुआ है। आपको क्या परेशानी टूरिस्ट होम बनाने में हो रही है, आप उसका टूरिस्ट महत्त्व का स्थल क्यों नहीं बनाते?

श्री सभापति : सेंटर लैंड एक्वायर कर सकता है, क्या आपके पास कोई श्वादी है?

श्री माधव राव सिधिया : सभापति महोदय, जैसे मैंने बताया कि हम लोग बहुत ज्यादा इच्छुक हैं कि वहाँ टूरिस्ट कम्प्लेक्स बनाया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बहुत प्रयास करना चाहते हैं और धृष्टता भी कर रहे हैं। परन्तु टूरिस्ट होम हवा में नहीं बनाया जा सकता है। जब तक हम को जमीन न मिले और यह स्टेट गवर्नमेंट के अन्तर्गत आता है। स्टेट गवर्नमेंट उसका अधिग्रहण कर के हम को हैंड ओवर करे तो हम टूरिस्ट कम्प्लेक्स बना देंगे।

श्री संघ प्रिय गौतम : स्टेट गवर्नमेंट को आप एडवॉस कम्पेसशन जमा कराइये, पैसा दीजिए (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव : सभापति जी, गौतम जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। महात्मा बुद्ध का संदेश जो उन्होंने पूरे विश्व को दिया था, केन्द्र सरकार ने जिस तरह से उस स्थान पर पर्यटन विकास को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लिया था उस निर्णय के आधार पर जमीन के अधिग्रहण की कार्यवाही भी शुरू हुई लेकिन कुछ रोक लग गई। फिर एक टीम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा भेजी गई। उस ने इस बात का प्रयास किया कि कहीं दूसरी जगह पर वहाँ जो पी०डब्ल्यू० बी० का इन्स्पेक्शन हाऊस है, निरीक्षण भवन है, उसको एकबापर करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। इस तरह की केन्द्रीय सरकार की मंशा है कि महात्मा बुद्ध जैसे महान् दार्शनिक, धर्म के अग्रणी को स्मरण करने के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनकी सम्मान देने के लिए इस तरह की यहाँ व्यवस्था की जाए। माननीय मंत्री जी ने यह भी अपने उत्तर में कहा कि हमने नवम्बर, 1988 से ले कर सितम्बर, 1990 तक बहुत से रिमाइंडर भी भेजे लेकिन प्रदेश सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। मैं यह जानना चाहूँगा कि जब इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार भी चिंतित है तथा हमारे सम्मानित सदस्य गौतम जी और दूसरे भी जानते हैं जिनकी सरकार वहाँ पर है तो क्या मंत्री जी द्वारा इतने रिमाइंडर भेजने के बाद, वहाँ पर पर्यटन स्थल के विकास को ध्यान में रखते हुए, महात्मा बुद्ध की उस स्थली का जिस तरह से विकास करना चाहते हैं, इस गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए क्या आप उत्तर प्रदेश के ट्यूरिज्म मंत्री को बुला कर के या उनके साथ बैठ कर के इस प्रश्न को जल्दी हल करेंगे? मेरे प्रश्न का भाग (ब) यह है कि क्योंकि इस में इतना विलम्ब हो रहा है इसलिए विलम्ब के आधार पर एक बार बैठ कर निर्णय ले लिया जाना चाहिये। यह भी बिलकुल सही बात है कि यह जापान से मिली हुई योजना है क्योंकि जापान में आज भी

जिस तरह से बुद्ध धर्म की पूजा होती है और उनकी एक योजना भी है। इसको ध्यान में रखते हुए इस बात को जल्दी से तय करा के सदन को आश्वस्त करेंगे कि हम इतने दिनों तक इस निर्माण कार्य को सारी बाधाओं को दूर करने के बाद पूरा करने की दिशा में प्रयास करेंगे और सदन को भ्रवगत कराने का प्रयास करेंगे? मेरे प्रश्न का भाग (स) यह है कि जमीन जो नहीं मिल पा रही है उस जमीन को जल्दी से जल्दी लेने के लिए क्या आप प्रदेश की सरकार को जो धनराशि दी जाती है वह दे कर के उसको इस लायक बनाने का काम करेंगे ताकि वह आपके ऊपर आरोप न लगा सके?

श्री माधव राव सिधिया : सभापति महोदय, हमें कोई धनराशि राज्य सरकार को नहीं देनी है। उनको यह जमीन निशुल्क देनी है। इसलिए उनकी जो जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है उसे जल्दी से निबटा लें और इस ओर निश्चित रूप से जैसे माननीय सदस्य ने कहा हम लोग पूरी तरह से तत्परता के साथ उनसे मिलने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कुछ सुनवाई करेंगे हालांकि हम आठ-दस बार उनको लिख चुके हैं। शायद प्रत्यक्ष रूप से हमारे कुछ सुनवाई हो। दूसरी बात जो आपने पूछी थी, आप तीन चार सवाल पूछ चुके हैं।  
(व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव : हमने प्रश्न को (अ), (ब) और (स) कर के पूछा है। हमने यह भी पूछा था कि कब तक आप ट्यूरिज्म मंत्री से मिल कर के इस बात का निर्णय कर लेंगे। आप सचमुच यह कार्य जिस गम्भीरता से कर रहे हैं, इस गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए कब तक आप निर्माण करा लेंगे?

श्री माधव राव सिधिया : इसके बारे में मैं निश्चित रूप से फिर लिखूँगा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जब भी के दिल्ली आने के लिए तैयार

है, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, इस पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक टारगेट या लक्ष्य निर्धारित करने का सवाल है। टारिफ़ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो नीति निर्धारित कर सकता है और अपनी इच्छुकता व्यक्त कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट से चर्चा कर सकता है पर अंतर्गतवा मुख्य जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है क्योंकि लैंड, पावर, कंस्ट्रक्शन में सब बातें स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं और कई बार हमको दिक्कतों और कठिनाइयों को सह्यूस करना पड़ता है अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को क्रियान्वित करने में, इसीलिए कोई टारगेट (व्यवधान)

श्री राय नरेश यादव : कब तक बात ही जायेगी क्योंकि मामला बहुत गम्भीर है।

श्री सभापति : ये कैसा बता सकते हैं ?

इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबन्ध

\* 342. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :

क्या शिक्षित मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इराक पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण वहाँ दवाइयों और खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता के कारण लाखों बच्चे और वृद्ध व्यक्ति मर रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को इस संबंध में लिखा है

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAV SINH SOLANKI) : (a) Government is aware of the serious situation within Iraq caused by UN economic sanctions against that country and the acute shortages of essential commodities, including food and medicines.

सभा में यह प्रश्न श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल द्वारा पूछा गया।

(b) Being alive to the humanitarian aspects of the situation, India has consistently advocated at the United Nations Security Council, easing of sanctions against Iraq, which would enable imports into Iraq of food, medicines and other essential commodities.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मोहतरिम नेयरमैन साहब, आपकी तबस्सत में मैं वजीरे खारिजा में जो जवाब दिया है उसके बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ तवज्जह दिलाकर इनमें कुछ पूछना चाहता हूँ। मोहतरिम वजीर ने जवाब दिया है कि हुकूमते हिंद इस बात से बाखबर है कि इराक के अंदर बूढ़े, जवान और बच्चे बीमारी से, दवाइयों की कमी से और खाने पीने की चीजों की कमी की वजह से मारे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर बराबर इस बात की कोशिश हुकूमते हिंद की तरफ से होती रही है कि वहाँ जो परेशानी है, इराक के अंदर, उसको कम करने की कोशिश की जाए और दवाइयाँ और खाने की चीजें वहाँ एक्सपोर्ट हो सकें या वहाँ तक पहुँच सकें। इसकी सरकार ने वकालत की है। मैं इसी संबंध में इसी ताल्लुक से मोहतरिम वजीर से यह पूछना चाहूँगा कि मुजिश्ता दो हफ्ते पहले हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के 51 मेम्बराने पार्लियामेंट ने एक मेमोरैंडम या एक एहतिनाजी खत यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को लिखा था। इसमें राज्य सभा और लोक सभा के 51 मेम्बराने पार्लियामेंट शामिल थे। इस पर दस्तखत करने वाली पार्टियों के नाम थे—जनता दल, सी०पी० आई० "एम०", सी०पी०आई०, डी०एम०के०, समाजवादी जनता दल और भारतीय जनता पार्टी.. (व्यवधान) मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि इस खत को बी०बी०सी० ने नश्र किया, वाइस आफ अमेरिका ने नश्र किया, दूरदर्शन ने भी नश्र किया। क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है और अगर जानकारी है तो इस सिलसिले में मंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस को लिखित रूप में क्या कार्यवाही की है या क्या रिक्वेस्ट की है वह बताना गवारा करेंगे ? लिखित रूप में उन्होंने क्या काम किया है। चूँकि सवाल का जवाब दिया है कि यूनाइटेड नेशंस में